भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1238

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का निजीकरण

1238 श्री संदोष कुमार पी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष में देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख में निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने का कोई प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन सहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। हालांकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए, जिसमें मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना या नई सुविधाओं की स्थापना करना शामिल है, आवश्यकता आधारित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के माध्यम से और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अपने समग्र संसाधन दायरे के भीतर अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में दिए गए प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीपीपी मॉडल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विवरण संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रबंधित और अनुरक्षित किया जाता है।

(ख) और (ग): एनएचएम के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं। सीआरएम की विभिन्न रिपोर्टों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में इस पर उपलब्ध है।

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=795&lid=195.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तरों पर स्वास्थ्य परिचर्या में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की समीक्षा की गई। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य परिचर्या में प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की प्रमुख विशेषताओं और उपायों की पहचान करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर उपलब्ध साक्ष्यों का आकलन करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और सीमाओं को समझना था। इस अध्ययन में 2005 से 2020 की अवधि के दौरान विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और डेटाबेस से भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी पर मौजूदा और उपलब्ध अध्ययनों/सामग्रियों की माध्यमिक डेटा समीक्षा शामिल थी। रिपोर्ट नीचे लिंक पर उपलब्ध है:

https://nhsrcindia.org/sites/default/files/2022-9/PPP%20BOOK%2027.05.2022_0.pdf

****